(d) The daily sales are deposited by the Florist with the CGIC. The cash memos are checked against cash receipts. The commission is deducted before payment of the balance to the contractor. The accounts and operations of the Florist Shop are subject to audit.

Loan given to M/s Oberoi for Hotels Abroad

6376. SHRI 'O. V. ALAGESAN: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a recent press Report saying that a huge loan of more than three crores of rupees has been given to M/s Oberoi for hotels abroad;

(b) if so, the nature and details of transactions including terms and conditions thereof; and

(c) the steps Government have taken to ensure the proper implementation of these terms and conditions ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK): (a) No loans have been given to M/s oberoi Hotels for their hotels abroad by Government of India..

(b) and (c). Does not arise.

महाराष्ट्र में रुई की एकाधिकार खरीद

6377. **श्री डी० जी० गवाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1975-76 में महाराष्ट्र में रुई की एकाधिकार खरीद के लिए अनुमति दी थी और यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि दी गई और क्या उक्त धनराशि ऋण अथवा सहायता के रूप में दी गई थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1977-78 में भी महाराष्ट्र को रुई की खरीद के लिए सहायता देने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि महाराष्ट्र सरकार रुई की खरीद बन्द कर देती है तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय रुई निगम के माध्यम से रुई की खरीद करने का है ; और

(घ) क्या प्राइवेट व्यापारियों को उक्त खरीद के लिए बैंकों से धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) महाराष्ट्र में रुई की एकाधिकार खरीद के लिए महाराष्ट्र कच्ची रुई (अधिप्राप्ति, प्रोसेसिंग तथा विपणन), अधिनियम 1971 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति अपेक्षित नहीं है । तथापि इस योजना के अधीन प्राप्त की गई रुई की गारंटीशुदा कीमतों के निर्धारण के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है । यह स्वीकृति 1975-76 में दी गई थी । रुई मौसम 1975-76 के लिए महाराष्ट्र सहकारी विपणन परिसंघ को 40 करोड़ रु० की ऋण सुविधा दी गई थी—20 करोड़ रु० महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से तथा 20 करोड़ रु० भारतीय रिजर्व बैंक से ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने 1977-78 रुई मौसम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से 60 करोड़ रु० की ऋण सुविधा के लिए अनुरोध किया है और इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है ।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र सरकार ने रुई एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना को अभी तक समाप्त नहीं किया है ।

Appointment of Grade II Clerks by Reserve Banks of India, Kanpur

6378. SHRI ZULFIQUARULLA: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether about 300 graduate candidates were selected and put on the waiting

list for appointment as II grade Clerks by the Reserve Bank of India, Kanpur in March, 1975 and the validity of the said list was extended upto 6th March, 1977;

(b) if so, whether fresh applications for similarposts were called in December, 1976 when 40 of the slected candidates on the waiting list had yet to be appointed and their claims for appointment were ignored; and

(c) if so, facts about the matter and the reasons for inviting fresh applications before the expiry of the validity of the waiting list ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H.M. PATEL): (a) to (c).Reserve Bank of India has reported that their Kanpur office prepared a waiting list of candidates for the post of Clerk/Com Note Examiner Grade II on 6th March, 1975. The list contained 345 candidates—282 belonging to general category and 63 belonging to Scheduled Caste category. The list was vaild for one year but since a large number of wait-listed candidates remained unabsorbed on the expiry of period of one year, Kanpur Office was permitted to keep the list vaild for further period of one year i.e. upto 6th March, 1977. The number of candidates who have remianed unabsorbed from the list despite extension of its validity upto 6th March, 1977 is 126.

Reserve Bank has further reported that since the preparation of a waiting list takes about 3 to 6 months in order to have the new list ready by 6th March, 1977 viz. the date of expiry of the extended term of the earlier list, its Kanpur Office issued an advertisement in December, 1976 for the purpose.

बिड़ला उद्योग समूह द्वारा माल का आयात

6379. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों मे वर्षवार बिड़ला समूह उद्योग द्वारा निम्नलिखित ऐसी विदेशी कम्पनियों से, जिसमें बिड़ला बन्धुओं के शेयर हैं, कितने मूल्य का माल आयात किया गया ;

(1) पी० टी० ग्रौरीजिन सिन्टैक्स इंडोनेशिया,

(2) इंडोपील टैक्सटाइल मनीला,

(3) पी० ए० एन० ग्रफरीकन कन्सलटैंसी सर्विस (एन० ग्राई० जे०) लिमिटेड,

(4) नाईजीरिया इंजीनियरिंग वर्कस लिमिटेड, ग्रौर

(5) पी० टी० होरिजन सिन्टैक्स इंडोनेशिया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : वास्तविक ग्रायातों के ग्रांकड़े वस्तुग्रों, एवं देशों के ग्रनुसार वाणिज्यिक जानकारी तथा ग्रंकसकलन महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा संकलित किये जाते हैं तथा मंथली स्टेटिस्टिक्स ग्राफ दि फारेन ट्रेड ग्राफ इंडिया, खंड 2 ग्रायातों में, प्रकाशित किये जाते हैं। जानकारी ग्रायातकों ग्रथवा उन फर्मों के ग्रनुसार नहीं रखी जाती है जिनसे ग्रायात किया जाता है।

Liquidation of Central Co-operative Banks in Assam

6380. SHRI PURNA SINHA: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that against the Government's decision to activise rural banks, the Government of Assam has ordered liquidation of the Central Co-operative Banks of Assam in every district of the State;

(b) if so, what steps Government are taking to activise the Central Co-operative Banks of Assam by financing them directly through the Reserve Bank of India in accordance with the policy decision announced in reply to the Starred Question No. 588 dated 22nd July, 1977; and

(c) whether the Reserve Bank of India suggested closure of the rural banks in consequence of its own anti-rural bank policy ?;

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). The Government of Assam, in consultation with the Reserve Bank of India, decided merge all their 7 Central Co-operative Banks with the Assam State Co-operative Banks as a part of the revitalisation scheme for co-operative credit structure in the State